May we know what is the report of price monitoring cell during this period of Rs.15 gap and what are the actions taken by the Government?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, usually we take Delhi as an example. Sir, on 9.12.2011 *i.e.,* three days back, in Delhi mandi, the price of tomato was Rs. 11 per kg. Sir, one week back, it was Rs. 13 per kg. But, one month back, it was Rs. 33 per kg. So, there is high fluctuation. There are various reasons. The reason behind high volatility was Diwali season which affected the arrivals of vegetables to mandi. Then, tomato is mainly produced in Andhra Pradesh. And, in view of the agitations taking place in Andhra Pradesh, there was some problem in the movement of trucks and rail transportation to many cities.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: No, no, Sir. It is not correct.

प्रो. राम गोपाल यादव: सभापति जी, टमाटर एक ऐसी सब्जी है, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती और सड़ जाती है। इस तरह के जितने भी perishable fruits and vegetables हैं, हिंदुस्तान में लगभग 50 हजार से लेकर 60 हजार करोड़ कीमत के फल और सब्जियां हर साल सड़ जाती हैं। इनकी प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि टमाटर को सुरक्षित रखने की व्यवस्था के अभाव में जो मूल्य वृद्धि होती है, उसको रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि उसको प्रोसेस किया जाए और उसको प्रिज़र्व किया जाए। क्या आपने इस संबंध में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से कोई चर्चा की है कि इसके लिए क्या किया जाए, जिससे हम इसको बचा सकें और इसकी कीमत को बढ़ने से रोक सकें?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, the Ministry of Agriculture, through the National Horticulture Board, is implementing a scheme called Capital Investment Subsidy for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Produce. The second one is: The Ministry of Food Processing has a number of schemes, including the RKVY, which is left to the State Governments for having value additions.

PROF. RAM GOPAL YADAV: Sir, it is only on paper.

कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण विद्युत-उत्पादन में व्यवधान पैदा होना

*263. **श्री रवि शंकर प्रसाद** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2011-12 में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान ताप-विद्युत क्षेत्र में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण विद्युत-उत्पादन में व्यवधान पैदा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा संकट पैदा होने का पूर्वानुमान लगाया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण अप्रैल से अक्टूबर, 2011 के दौरान विद्युत यूटिलिटियों ने 5.3 बिलियन यूनिट की उत्पादन हानि की रिपोर्ट की है। ताप विद्युत केंद्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से देश में घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

(ii) विद्युत युटिलिटियों को कोयले की आवश्यकता और घरेलू स्रोतों से इसकी उपलब्धता के बीच की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने की सलाह दी जा रही है।

(iii) कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय में संबंधित मंत्रालयों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल इंडिया लिमिटेड तथा एनटीपीसी के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न स्तरों पर कोयले की आपूर्ति की समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वर्ष आधार पर कोयले की कमी का अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 2011-12 के लिए 455 मिलियन टन (एमटी) की अनुमानित कोयले की आवश्यकता की तुलना में घरेलू स्रोतों से कोयले की उपलब्धता 402 एमटी बताई गई थी इसके परिणामस्वरूप 53 एमटी कोयले की प्रत्याशित कमी रही। इस अंतर को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को वर्ष 2011-12 के दौरान कोयले के साथ मिश्रित करने के लिए 35 मिलियन टन (उच्च कैलोरिफिक गुणवत्ता के कारण 53 एमटी घरेलू कोयले के बराबर) कोयला आयात करने का लक्ष्य सौंपा गया है। अप्रैल से अक्टूबर 2011 तक विद्युत यूटिलिटियों ने 18 एमटी कोयले का आयात किया।

Interruption in power generation due to inadequate supply of coal

†*263. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that power generation has been interrupted due to inadequate supply of coal in thermal sector during the period from April to October of the year 2011-12;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether Government had anticipated this crisis; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During April to October, 2011, Power Utilities reported a generation loss of 5.3 Billion Unit due to inadequate availability of coal. Following steps have been taken by the Government to augment supply of coal to thermal power stations:

(i) Ministry of Coal / Coal India Ltd. (CIL) are being continually pursued to enhance production of domestic coal in the country.

(ii) Power Utilities are being advised to import coal to bridge the shortfall between requirement of coal and its availability from the domestic sources.

(iii) The coal supply position is reviewed at various levels in Ministry of Coal, Ministry of Power and Cabinet Secretariat with participation from the concerned Ministries, CEA, Coal India Limited and NTPC.

(c) and (d) Demand of coal is estimated on a year to year basis and shortage of coal is assessed depending upon the availability of indigenous coal. For the year 2011-12, against estimated requirement of 455 Million Tonne (MT), coal availability from the domestic sources, was indicated as 402 MT, thereby resulting in an anticipated shortfall of 53 MT coal. In order to bridge this gap, Power Utilities were assigned a target to import 35 MT (equivalent to 53 MT of domestic coal due to its higher calorific value) of coal during the year 2011-12 for blending with domestic coal. During April to October, 2011, the Power Utilities imported 18 MT coal.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, यदि कैबिनेट मिनिस्टर साहब मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि 2011-12 में आपके बिजली प्रोडक्शन का क्या टारगेट था और कितना लॉस हुआ? आपने अपने उत्तर में कहा कि अक्टूबर तक 5.3 बिलियन यूनिट्स का लॉस हुआ है। अच्छा होता यदि इसे आप मैगावाट में बताते। मैं जानना चाहूंगा कि मार्च तक कितना लॉस होगा? आपने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि कोल इंडिया से आपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। संयोग से यहां माननीय कोयला मंत्री भी मौजूद हैं। हम अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन देखते हैं कि कोल इंडिया का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, उसके कारण

उनकी तारीफ होती है और यहां इतना बड़ा mismatch आप review करते हैं। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी आपने जो टारगेट बताया है, उसमें कितना लॉस होने वाला है और वह लॉस कम हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति जी, यह जो बिजली का लॉस बताया जाता है, यह हमेशा बिलियन यूनिट्स में बताया जाता है और इसलिए हमने बिलियन यूनिट्स में बताया है। यह करीब कितने मैगावाट होगा, यह फिगर मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। Usually it is the practice to give loss of power in units and that is the reason why I have given the figure in units. यह बात सही है कि आजकल कोयले का उत्पादन लगभग 1% कम चल रहा है और यह बात भी सही है कई दिक्कतें उनको भी आ रही हैं, कहीं स्ट्राइक हो रही है, कहीं खदानों में पानी घुस गया है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से यह सब हो रहा है। पूरा देश यह जानता है कि कोयले का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसके लिए हमने 10 to 15 per cent and upto 20 per cent imported coal को मिक्स करने का प्रयास किया है, ताकि बिजली का उत्पादन इस देश में होता रहे और जिस रफ्तार से हम काम करना चाहते हैं, वह हो सके। मैंने अभी-अभी बताया था कि जिस तरह से बिजली कपैसिटी अडिशन हो गई है, हमने यह नहीं सोचा था कि इतना कोयला लगेगा, तो अभी प्रोडक्शन बढ़ाने का काम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी तुरंत एक बैठक ले रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी को भी इस कोल शॉर्टेज के बारे में बैठक लेने के लिए कहा है और वे भी बैठक ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि जैसे 2010-11 में हमने 12 हज़ार मेगावॉट करने का प्रयास किया है, वह हम कर सकेंगे। 2011-12 में आज तक 10,308 मेगावॉट हो गया है और अभी मेरे हाथ में तीन महीने बाकी हैं, तो मैं कर पाऊंगा। सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने जब इस हाउस में बताया था कि 12 हजार मेगावॉट एक साल में पैदा किया और 15795 मेगावॉट synchronize किया था, तो हम उस रिकॉर्ड पर चल रहे हैं और हम आपको यह आश्वासित करते हैं कि इस देश को बिजली देने का काम इस साल भी हम ज़रूर करेंगे।

RE: WELCOME TO PARLIAMENT DELEGATION FROM MYANMAR

MR. CHAIRMAN: Can I seek your indulgence for a minute? I have an announcement to make. We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from Myanmar, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency, Mr. Thura U Shew Mann, Speaker of Pyithu Hluttaw, the Lower House of the Parliament of Myanmar. On behalf of the Members of the House and on my own behalf I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the Delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people and that their visit to this country

will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Myanmar.Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Myanmar.

प्रश्न संख्या 263 (क्रमागत)

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, मुझे इस बात का संतोष है कि आपने सदन में स्वीकार किया कि कोल का उत्पादन माइनस में है। जो विज्ञापन हम देखते हैं, वह सच्चाई नहीं है। आपने अभी पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि कोयला पावर जो है, वह Constitution में Concurrent List में है, हम जानते हैं। तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि कोल ब्लॉक के लोकेशन में चाहे वह मध्य प्रदेश हो, छतीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, इनको परेशानी आती है। मध्य प्रदेश के सांसदों को राष्ट्रपति को memorandum देना था, ठीक है, पावर उनका अधिकार है, लेकिन कोयला ब्लॉक देना आपका अधिकार है और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा - सारे कोल ब्लॉक वहीं पर हैं। वहां की जनता विपक्ष को वोट देती है, आपको नहीं, तो इसके कारण क्या आप अच्छे कोल ब्लॉक देंगे नहीं और कहेंगे कि वे पावर पूरा नहीं करते हैं? ऐसा कैसे चलेगा? इसके बारे में संघीय ढांचे के अनुसार हम आपसे एक स्पष्ट कमिटमेंट चाहेंगे कि क्या सारी प्रदेश सरकारों को, उनका राजनीतिक रंग कुछ भी हो, आप कोल ब्लॉक समय से, उनकी मांग के अनुसार देंगे? इसका यह उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति जी, कई ऐसे प्रांत हैं जहां ऐसी खदानें बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन कई ऐसी स्टेट्स हैं, जहां खदानें नहीं हैं। जहां खदानें हैं, उनको देने की और बाहर के राज्यों को भी देने की पॉलिसी रही है और उन माइन्स का बहुत स्टेट्स में बंटवारा भी हो गया है। 10th Plan में और 11th Plan की beginning में बंटवारा हो गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: क्षमा करेंगे मंत्री जी, आप सही नहीं बोल रहे हैं। मैं interrupt नहीं करता हूं। यहां मध्य प्रदेश का delegation लेकर राष्ट्रपति जी के यहां मैं भी गया था। बिहार की समस्या मैं जानता हूं, झारखंड की समस्या मैं जानता हूं, उड़ीसा की चर्चा कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)... हर जगह discrimination हो रहा है कोल ब्लॉक्स को लेकर। ...(**व्यवधान**)...

SHRI N.K. SINGH: Sir, there is a heavy discrimination.

श्री सभापति: प्लीज़ ... प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: क्षमा कीजिए, यह सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती माया सिंह: सर ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह आप सही नहीं बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... Please sit down. बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... One minute please.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, the States are being discriminated in this matter. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: हमें कोयले के खदान नहीं दिए जाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: मंत्री जी, आप ...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: उत्तर प्रदेश के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। ...(**व्यवधान**)... वहां भी ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा: हर जगह कोल ब्लॉक का घोटाला होता है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a serious thing. ...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Except a few States. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute. I think, this is a subject. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, it is a serious issue. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. One minute. ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक: कोयला मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We want your protection, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Just one minute please. If the Members so desire, they can give notice for a discussion on this subject. This is a question, to which an answer is being given. If the answer is not. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: What is the answer being given? That's the query. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have not heard the complete answer. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Coal is being imported from Australia when good quality coal is available here. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आपका सवाल नहीं था। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, I have been very particular in telling. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: There are other questions to be answered also. ...*(Interruptions)*...

श्री ब्रजेश पाठक: सर, सदस्यों को संरक्षण चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: वहां भेदभाव होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पाणि जी, प्लीज़ बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती माया सिंह: सर ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, Maya Singh ji. ...*(Interruptions)*... It was not your question. ...*(Interruptions)*... It is not your question. Please sit down. आपका प्रश्न नहीं था। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. आपका सवाल नहीं था, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... माया सिंह जी, आप भी बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, first of all. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, first of all, it is a question of the Coal Ministry, and, the Power Ministry recommends the cases as and when it receives the applications. In the past, we have recommended linkage and the coal blocks. Our job is to just recommend and the job of the allotment is of the Coal Ministry. ...*(Interruptions)*... It is not. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: What is this, Sir? ...*(Interruptions)*...

PROF. RAM GOPAL YADAV: He is also sitting here. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I must bring it to the notice of the House that considering this difficulty, in the Twelfth Plan, we have recommended a linkage of 1,25,000 MW ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: यह मत करिए। This is completely unacceptable. ...*(Interruptions)*... Don't disrupt. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... This is unacceptable behaviour. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: अभी भी होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: कम से कम वे सही जवाब तो दें। It is a serious issue, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप यहां मत आइए। ...(**व्यवधान**)... Mr. Pany, I will name you. Go back, otherwise, I will name you. I am warning you. ...*(Interruptions)*...

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Discrimination against States is there. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a big scam. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, I have told very categorically that our job is to recommend the linkage. ...*(Interruptions)*... Many States have blocks but they are not working on it. ...*(Interruptions)*... Sir, I have not understood what exactly they wanted. ...*(Interruptions)*... I am replying to their question. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, please allow a discussion on coal block allotment to non-users. ...*(Interruptions)*... People are forced to import coal whereas good quality coal, high calorific value coal, is available in the country. But people are unable to use it because that is sanctioned to the people who are not using it but black-marketing it for ईंट का भट्ठा। ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Ahluwalia sahib, you know the procedure very well. ...*(Interruptions)*... If you want a discussion, please give notice for it. ...*(Interruptions)*... Don't seek a discussion under the guise of a question. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, we will give a notice.

MR. CHAIRMAN: That is not the way to give notice from the floor. I am distressed at the behaviour of the Members of the senior House of Parliament. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, we are here to get the answer from the Government. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: But this is not the way to seek answers. ...*(Interruptions)*... I would like to put a question to the House. ...*(Interruptions)*... I would like to put a question to the House. Does this House wish to have a Question Hour as such?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Or does it wish to do away with it? ...*(Interruptions)*...

DR. FAROOQ ABDULLAH: This is what I only want to request all. Sir, we are ready to answer the question. If there is some problem in our answer, as you quite rightly said, you can ask for a discussion on it. I think that this is the best way. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Don't mislead the House. ...*(Interruptions)*...

DR. FAROOQ ABDULLAH: You are quite right to ask the question. You are quite right to get the answer. And if you are not satisfied with the answer. ...*(Interruptions)*... Please use democratic method. Don't get into the centre of the well. ...*(Interruptions)*... कोई एक बात करे तो हम सुन सकते हैं, आप तो इतने लोग बात कर रहे हैं कि हम सुन ही नहीं सकते कि आप क्या बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, we will give a notice. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Can we now get on with supplementaries to this question? Let the supplementary be answered.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, first of all, this department belongs to the Coal Ministry. However, I was replying to the question of the hon. Member that our job is to recommend coal blocks according to the demand.

We recommend linkages and blocks for consideration and allotment by the Coal Ministry. But I must bring it to your notice and I have been seeing for the last six years, coal blocks which were distributed in 2001, 2002 and 2003, mining has not yet been started. So, the Coal Ministry has issued notices to such people either to return or start the work. As far as coal blocks which were given to the States of Madhya Pradesh and Bihar are concerned, we have sent our recommendations to the Department. It is not that we have not sent the recommendations. For mining it takes 5-6 years. Once mining is allotted, environmental clearance and forest clearances have to be obtained. So far, the mining has just started in a few blocks. It takes 5-6 years.

MR CHAIRMAN: Dr. Mungekar please. ...*(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: Issue some rule that the Minister must come prepared. ...*(Interruptions)*... आपको क्या आपत्ति है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप जरा बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY: Mr. Chairman, Sir, may I know from the hon. Minister whether Coal India Ltd. is not able to supply committed amount of coal to several power generating

stations? May I also know whether shortage of railway wagons to transport coal to the power stations is affecting power generation? In fact, during rainy season, coal remains unprotected and gets wet. As a result, power generation is not possible.

MR. CHAIRMAN: One question please.

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY: It is part of the one question.

MR. CHAIRMAN: No. One question.

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY: Is it a fact that private players are getting priority in the supply of coal over the public sector power stations?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: In fact, the question does not pertain to my Ministry. However, as the Power Minister, I am aware of the problem and I am facing difficulties to get coal. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: As the hon. Member said, due to rain coal gets wet and due to non availability of wagons coal does not reach power stations in time, it is a fact and that is why there is a approximately minus one per cent negative growth. If we get coal, we can generate more power. The Coal Minister is also trying his best to improve the situation. Suddenly, the growth in power generation capacity gone up. That is why we are facing difficulty.

MR. CHAIRMAN: Shri Ratanpuri.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Shri Shriprakash Jaiswal wants to reply.

MR. CHAIRMAN: Shri Ratanpuri, just one minute. Let Shri Prakash Jaiswal reply.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, हालांकि हमारा यह क्वेश्चन नहीं था, लेकिन माननीय सदस्यों की तरफ से आशंका प्रकट की जा रही है। दो-तीन मूल बातें हैं जिन्हें माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। पहली बात तो यह है, माननीय सदस्यों का कहना यह है कि साहब जिन स्टेट्स में कोल पैदा होता है, उन स्टेट्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर पुंज: हमने कहा कि गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ भेदभाव होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति जी, देश के केवल 30 परसेंट हिस्से में कोल पैदा होता है और हमें सप्लाई पूरे देश में करनी होती है। इस तरह की बात कही जाए कि कोल उड़ीसा में पैदा होता है, इसे आप दूसरे स्टेट्स को क्यों देते हो और मध्य प्रदेश को फायदा होता है, और दूसरी स्टेट्स को ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर पुंज: यह कौन कह रहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, ...(**व्यवधान**)... सर, मैं यह ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, ये कैसी बात करते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मंत्री जी पूरी तरह से ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़, प्लीज़, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, गेहूं पंजाब में पैदा होता है और पूरा देश खाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, उड़ीसा में कोयले का उत्पादन होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस स्टेट में कोयला पैदा होता है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: पाणि जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उस स्टेट को दूसरी स्टेट से ज्यादा कोयला दिया जाता है। ...(**व्यवधान**)... ज्यादा कोल ब्लॉक दिए गए हैं, ...(**व्यवधान**)... ज्यादा कोल के लिंकेज़ दिए गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप नोटिस दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैं कितनी बार कहूं कि आप पहले नोटिस दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, मंत्री जी कहां की बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप नोटिस दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह कहना कि भेदभाव किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। ...(**व्यवधान**)... हमारे माननीय सदस्यों के दिमाग में दूसरा संशय यह है ...(**व्यवधान**)... Sir, thank you.

MR. CHAIRMAN: Yes, please go ahead, Mr. Ratanpuri.

SHRI G.N. RATANPURI: Sir, the NHPC has commissioned its first unit with a capacity of 15 megawatts at Chutuk, Kargil. But it has failed to put in place the transmission and distribution system which was entrusted to it under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana. Under this Yojana our State has not completed more than 50 per cent target, but the allocation has been reduced as

compared to the previous years. Again our State is among the States which have the highest transmission losses. We have submitted certain projects to revamp the transmission and distribution system in the State. I would like to know from the hon. Minister whether he knows that the power which can be used in Kargil is not being used. We are not in a position to use it because NHPC has failed to put in place the transmission and distribution system and whether he will expedite the projects to reduce the transmission and distribution loss in Jammu and Kashmir.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, it is a little difficult there and the work has been going on. But I accept the anxiety of the hon. Member and I will ask the officers of the NHPC to speed up the work. We will take cognizance of it because we need to concentrate more on this border area and we will take care of it.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ: सर, कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण विद्युत उत्पादन व अन्य उत्पादन प्रभावित होने की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कोयला आबंटन में पिछला कितना बकाया है अर्थात् यह कितना बचा हुआ है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: कोयले का प्रश्न है इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता सकूंगा। चाहे मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या जहां पर भी खदानें हैं वे कोयले से संबंधित हैं।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 264. I think we have spent more than half-an-hour on one single question.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, मैं बहुत बेसिक बात बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: रामदास जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप जाइए, बैठ जाइए।

Efficacy of Public Distribution System

*264. SHRI BAISHNAB PARIDA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, according to the Chief Economic Advisor, Government of India, 44 per cent of the foodgrains meant for the poor never reaches them through the Public Distribution System; and

(b) if so, whether Government is mulling over to change the system of distribution by giving foodgrains directly to the poor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.